लाख रुपया खर्च हो। और गोदाम 11.08 हैं जिसे पर कि 6,101.360 लाख रुपया खर्च होगा और ये सभी काम इस सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर पूरे हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।

T. V. Facilities in Hostels

*150. SHRI AJIT P. K. JOGI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the inmates of tribal and scheduled caste hostels in interior and backward areas, do not have the facility to watch Television and thereby remain cut off from the day to day developments; and

(b) if so, whether Government propose to provide at least one black and white television set to each tribal and scheduled caste hostel?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WELFARE (DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI): (a) and (b) A Centrally Sponsored Scheme has been in operation from 1987-88 for providing Television sets to primary and upper primary schools. Besides in many States Television sets have been installed in remote areas under community viewing schemes. However, there is no scheme for providing T.V. Sets to the Hostels.

श्री सभापति : आपका है।

DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI: First of all, I express my apologies to the House that I was late by two minutes.

श्री अजीत जोगी : मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में जिस विशेष केन्द्रीय सहायता का उल्लेख किया है उसका संबंध शालाओं से है जबकि मैंने प्रश्न आदिवासियों और हरिजनों के छात्रावासों के संबंध में किया था। इस प्रश्न की अहमियत इसलिए कि क्योंकि जैसा कि सब जानते हैं कि आदिवासी क्षेत्र अन्तराल के अन्दरूनी क्षेत्रों में हैं और न तो वहां के छात्रों ने कभी कार देखी है, न रेल देखी है। जो भी आधुनिक विकास हुआ है उससे उनका कहीं साक्षात्कार नहीं हुआ है। इसलिए मैंने अपने प्रश्न के माध्यम से यह जानना चाहा था कि आदिवासियों और हरिजनों के जो छात्रावास है क्या वहां सस्ते ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन सैट्स दिये जायेंगे जिससे जो कुछ आज संसार में हो रहा है उसका ज्ञान इन छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को मिल सके? मैं यह जानना चाहूंगा कि जब टेलीविजन उनकी शिक्षा के लिए, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए इतना लाभकारी हो सकता है तो क्यों नहीं हमारा कल्याण मंत्रालय एक इतनी छोटी सी चीज उन छात्रावासों को देने पर विचार करता है? क्यों नहीं जो दूसरा अपव्यय हो रहा है उनको काट कर यह जरूरी चीज हम रे आदिवासी हरिजन छात्रावासों को दिया जा सकता है?

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : माननीय सभापति जी, जहां तक छात्रावासों की बात है हमारी स्कीम के अंदर यह शामिल नहीं है लेकिन जो नार्दन-ईस्टर्न स्टेट्स जहां पर कि कम्यूनिटी की स्कीम हैं वहां पर सामाजिक तौर पर देख सकते है। यह पब्लिक प्लेस में रखकर, पंचायत घर में रखकर वहां के लोगों को दिखाया जा सकता है। अरुणाचल में 460, असम में 1500, मणिपुर में 570, मेघालय में 630, मिजोरम में 160, नागालैण्ड में 650 और त्रिपुरा में 1030 हैं। इस तरह से टोटल 5000 हैं। इसके अतिरिक्त दो-तीन और स्कीमें जिसका लाभ इन क्षेत्रों में रहने वाले रिमोट एरियाज के ट्राइबल्स को मिलता है। आन्ध्र प्रदेश में कम्यूनिटी व्युइंग सैणस 417 हैं, डिस्ट्रिक्ट लैवल सैट्स 400 हैं इस तरह से 8 17 हुए? बिहार में 320 कम्यूनिटी व्युइंग सेट्स हैं और 300 डिस्ट्रिक्ट लेवल के सेट्स हैं और 400 वी०एच०एफ० सेट्स हैं। इस तरह से ये 1020 हुए। इसी तरह से गुजरात में 756,300 और 400 हैं। टोटल 1456 हुए। हिमाचल में 17, जे एंड के में 550, कर्नाटक में 260, मध्य प्रदेश में 280 हैं और उड़ीसा में 279 और 400 डिफरट वैराइटीज के हैं जिनका

लभ कम्युनिटी को मिलता है। छात्रावास में जरूरी नहीं है ये लगे लेकिन इसी तरह पूरे स्टेट्स में है। करीब-करीब सब मिल कर नार्दर्न-ईस्टर्न स्टेट्स और अदर स्टेट्स में 22 जगह पर हैं।

श्री अजीत जोगी : जो जानकारी मंत्री महोदय ने अभी दी है यह आदिवासी और हरिजनों के क्षेत्रों के विषय में है जबकि मेरा प्रश्न मुख्यतया आदिवासी और हरिजन छात्रावासों से सम्बन्धित है। उन्होंने स्वयं कहा है छात्रावासों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है इसलिए जो भी आंकड़े आपने दिये हैं उनका सम्बन्ध छात्रावासों में अध्ययनरत छात्रों से नहीं है। मैंने प्रश्न यह किया था कि इन छात्रावासों में यह उपलब्ध क्यों नहीं कराये जा सकते हैं।

मैं अपना दूसरा पूरक प्रश्न इस रूप में पूछना चाहता हूं कि जब सामान्य छात्रों के छात्रावास में अधिकतर हर स्थान पर टेलीविजन सेट्स उपलब्ध है तो क्यों नहीं आदिवासी और हरिजनों के छात्रावासों में ये सेट्स उपलब्ध कराये जा सकते हैं जबकि यह इनके लिए ज्यादा जरूरी हैं? इस तरह का भेदभाव क्यों हमारे इन छात्रों के साथ किया जा रहा है? यदि ऐसा हो रहा है जो कि यथार्थ है तो इसको कल्याण मंत्रालय दूर क्यों नहीं कर रहा है?

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : माननीय सभापति जी, जहां तक सवाल है होस्टल्स का हमारा एकोमोडेशन प्लस एंसिलियरी फेसिलिटीज के अन्तर्गत जिसमें डाइनिंग हाल, किचन, कम्युनिटी ब्लाक आदि सब मिलाकर 12775 रुपये देते हैं। आधा स्टेट गवर्नमेंट देती है और आधा हम लोग देते हैं।

श्री अजीत जोगी : एक-एक हजार रुपया और दे दिया जाय तो काम हो जायेगा। यह भेदभाव नहीं होना चाहिए।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : तो इसमें भेदभाव की कोई बात नहीं है। 50 परसेंट हम देते हैं और 50 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट्स होस्टल के लिए देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो भी सहायता देना चाहे अपनी तरफ से दे सकती है। इसमें भेदभाव की कोई बात नहीं है।

कुमारी सईदा खातून : सभापति जी, मैं माननीय मंत्राणी जी से जानना चाहती हूं... (व्यवधान)

श्री सीताराम केसरी : "मंत्राणी जी" नहीं, "मंत्री महोदया" कहिये।

कुमारी सईदा खातून : ठीक है। मैं माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहती हूं कि आदिवासी और हरिजन क्षेत्रों में छात्रावासों के लिए जो टेलीविजन सेट दिये जाते हैं, क्या उनके संबंध में आपने कोई सर्वे कराया है कि उन क्षेत्रों में बिजली भी है या नहीं, क्योंकि अगर उन क्षेत्रों में बिजली नहीं है तो ये सेट्स उनके लिए बेकार हो जाते हैं? वे एक कमरे में बंद पड़े रहते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि पहले आप उनका सर्वे कराइये, जैसे मध्य प्रदेश में और दूसरी स्टेट्स में जहां पर आपने सेट दिये हैं, क्या वहां पर बिजली है? अगर वहां पर बिजली नहीं है तो पहले आप वहां पर बिजली पहुंचा दीजिये।

गृह मंत्री (श्री बूटा सिंह) : माननीय सभापति जी, मैं आपकी तरफ से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। कृपया आप सबकी जानकारी के लिए इसको स्पष्ट कर दें। माननीय, जो हमारे उत्तर देने वाले हैं वह "मंत्राणी" हैं या "मंत्री" हैं, कृपया आप इसको स्पष्ट कर दें... (व्यवधान)

श्री सभापति : यह तो कोई लैंग्वेज स्पेशलिष्ट, भाषाविद ही बता सकता है।

श्री बूटा सिंह : जनाब; यहां तो आपका ही आदेश चलता है।

श्री जगपाल सिंह ठाकुर : श्रीमन्, माननीय मंत्री महोदया कहना चाहिए नहीं तो सभी मंत्रियों की पत्नियां जो "मंत्राणी" कहलाती है मंत्री हो जाएंगी।

श्री सीताराम केसरी : "माननीय मंत्री महोदया" ठीक है ।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : माननीय सभापति जी, हमारे 119 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ट्राइबल्स हैं और ये अलग-अलग स्टेट्स में है जिनमे से 101 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक टी० वी० सेट्स जारी किये गये है । यह आशा की जाती है कि जहा पर टी० वी० सेट्स जारी किये जाते हैं वहां पर स्टेट गवनमेंट्स की तरफ से बिजली की व्यवस्था कराई जाये ।

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA: Mr. Chairman, Sir, I would like to know from the hon. Minister whether she has made a survey of the number of TV sets required for these schools and hostels. Supposing there are only 1,000 TV sets to be provided. I think, my hon. friend, Mr. Jogi, has a valid point. This is a small matter. It could be solved either by the Welfare Ministry or the Ministry of Information and Broadcasting. This should be solved. I would like to know from the hon. Minister whether any survey has been conducted. What is the number of sets and what is the cost involved?

DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI: Sir, this is to be done by the Information and Broadcasting Ministry. My Ministry has not done any survey in regard to this.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI H. K. L. BHAGAT): Sir, so far as the Ministry of Information and Broadcasting is concerned, I would like to add this for the information of the hon. Member. The hostels are dealt with by the Ministry of Welfare. My Ministry has decided to instal 5,000 TV sets in the seven States of the North-Eastern Region. About 1,000 sets have already been installed. I would not be able to give more detailed information. The Ministry of Education have studied the use of TV sets for educational purposes. I think, the Ministry is examining a proposal for putting up one lakh sets in schools. This is all I can say at the moment.

श्री भंवर लाल पवार : सभापति जी, जब भूतपूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने टेलीविजन का तीव्र गति से प्रचार और प्रसार करने के लिए कार्यक्रम बनाया तो उस समय हमारे विपक्षी लोगों ने उसकी आलोचना की थी और यह कहा था कि वे अपना प्रचार और प्रसार के लिए रास्ता निकाल रहो हैं ।

शिक्षा का अर्थ केवल अक्षर ज्ञान से नहीं होता है बल्कि मानसिक विकास भी है । प्रौढ़ शिक्षा पर सरकार अभी करोड़ों रुपया खर्च कर रही है । मैं माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रौढ़ शिक्षा पर खर्च की जानेवाली राशि मे से पिछड़े इलाकों के लिये टी० वी० सेट्स प्रोवाइड करके कोई ऐसा कार्यक्रम बनायगी जिसमें उनको जल्दी ही अच्छी शिक्षा दी जा सके ?

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : माननीय सभापति जी, हमने इन्फर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ बात करके ट्राइबल एरियाज के लिये सब प्लान बनाया है कि टी० वी० सेट और सेंटर इस तरह से बनाये जाएं जिससे प्रौढ़ शिक्षा और ट्राइबल्स के इन्वोल्वमेंट में मदद मिल सके ।

Outdoor recording in tribal areas would be encouraged so that they have a sense of involvement. Programmes would be chalked out which would be of relevance and interest to tribals particularly in areas of health, education and technology. Mere setting up of radio or TV stations in tribal areas is not enough. What is needed is a well worked out strategy for certain awareness about the various beneficiary programmes/schemes. These should be educative and infomative in rspect of various aspects having a bearing on tribal development.

There would be a small inter-ministrial committee comprising of officers of the Ministry of Information and Broadcasting and Ministry of Welfare representing tribal and Scheduled Caste divisions.

So, these are the programmes. इसके साथ जो हमारा रेजूकेशन...

श्री सभापति : संक्षेप में कह दीजिये ।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी एजूकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से इस साल 5 करोड़ रुपया रखा गया है। इसके अन्तर्गत 10 हजार स्कूलों में ये खासतौर से एजूकेशन परपज के लिये रखे जायेंगे। अभी तक 13 स्टेट्स में इसको युटिलाइज किया गया है। गुजरात, उड़ीसा, केरल, नागालैण्ड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, गोवा, दिल्ली, लक्ष्यद्वीप, दादरा, नागर हवेली में इसको इस साल और बढ़ाने जा रहे हैं ।

श्री सुरेश पचोरी : माननीय सभापति जी, हरिजन आदिवासी स्कूलों में टेलीविजन की उपलब्धता जो सरकार ने कराई है वह एक स्वागत योग्य कदम है । लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि टेलीविजन के कार्यक्रम का जो समय निर्धारित होता है उसमें महत्वपूर्ण कार्यक्रम, शिक्षा के कार्यक्रम सायकाल या रात्रिकाल में प्रसारित किये जाते हैं ताकि हरिजन और आदिवासी छात्र सांयकाल और रात्रिकाल में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से लाभांवित हो सकें और उन्हें विभिन्न विषयों की पर्याप्त जानकारी मिल सके । इसको मद्देनजर रखते हुये आशा है कि आदरणीय मंत्री महोदय इस सदन में घोषणा करें कि वे हरिजन-आदिवासी छात्रावासों में भी टेलीविजन उपलब्ध कराने के लिये प्रयास करेंगे । साथ ही सरकार ने अपने उत्तर में 101 इलाकों में टेलीविजन सर्विस प्रदान करने की बात कही है तो क्या सरकार ने इसको फिर से फीड कैंवे किया है और जो 101 जो उपलब्ध कराये गये हैं उनमें से अभी तक कितने काम कर रहे हैं ?

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : सभापति जी, जो स्पेशल प्रोग्राम ट्राइबल एरियाज के लिये डिजाइन किये गये हैं, इन्फर्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री की ओर से वे इस प्रकार बनाये गये हैं कि उनमें जो मसले फोकस करेंगे वह एजूकेशन, हैल्थ और रूरल टेक्नालाजी के ऊपर होंगे और ये स्कूल उसके अन्तर्गत रखे गये हैं । इसका उद्देश्य भी यही है कि स्कूलों में बच्चों को उनके माध्यम से शिक्षा दी जा सके और शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर इसका लाभ उठाया जा सके । यहां पर बार बार होस्टल का सवाल उठाया जा रहा है । अगर स्टेट गवर्नमेंट इसमें 50 प्रतिशत का जो अनुदान देती है तो उस 50 प्रतिशत में अगर स्टेट गवर्नमेंट टेलीविजन सेट दे सकती है तो हमारी तरफ से इसमें कोई एतराज नहीं होगा ।

SHRI H. K. L. BHAGAT: Sir, the hon. Members have asked a number of questions. Obviously, certain aspects for TV sets for hostels and tribal areas relate to Ministry of Welfare. Educational programmes are prepared by the Ministry of Education and broadcast by the Ministry of Information and Broadcasting.

MR. CHAIRMAN: They are telecast by you.

SHRI H. K. L. BHAGAT: I just wish to say that all the three Ministries...

MR. CHAIRMAN:... are working together.

SHRI H. K. L. BHAGAT:... Will try to sort out as best as we can, keeping in view the views which have been expressed by the Members.

MR. CHAIRMAN: Question No. 156.

*156. [*The questioner* (*Dr. Yelamanchili Sivaji*) *was absent. For answer* vide *col.* 38-39 infra].

Review of Functioning of (PDS) Public Distribution System.

*157. SHRI KAPIL VERMA: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) the number of meetings of the Advisory Council for Public Distribution System held to review the functioning of Public Distribution System during the last two years; and

(b) what steps Government propose to take or have taken to bring the consumer goods within the reach of the poor and for building a consumer protection movement?